कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष 61 अंक 3 मुम्बई फरवरी 2017

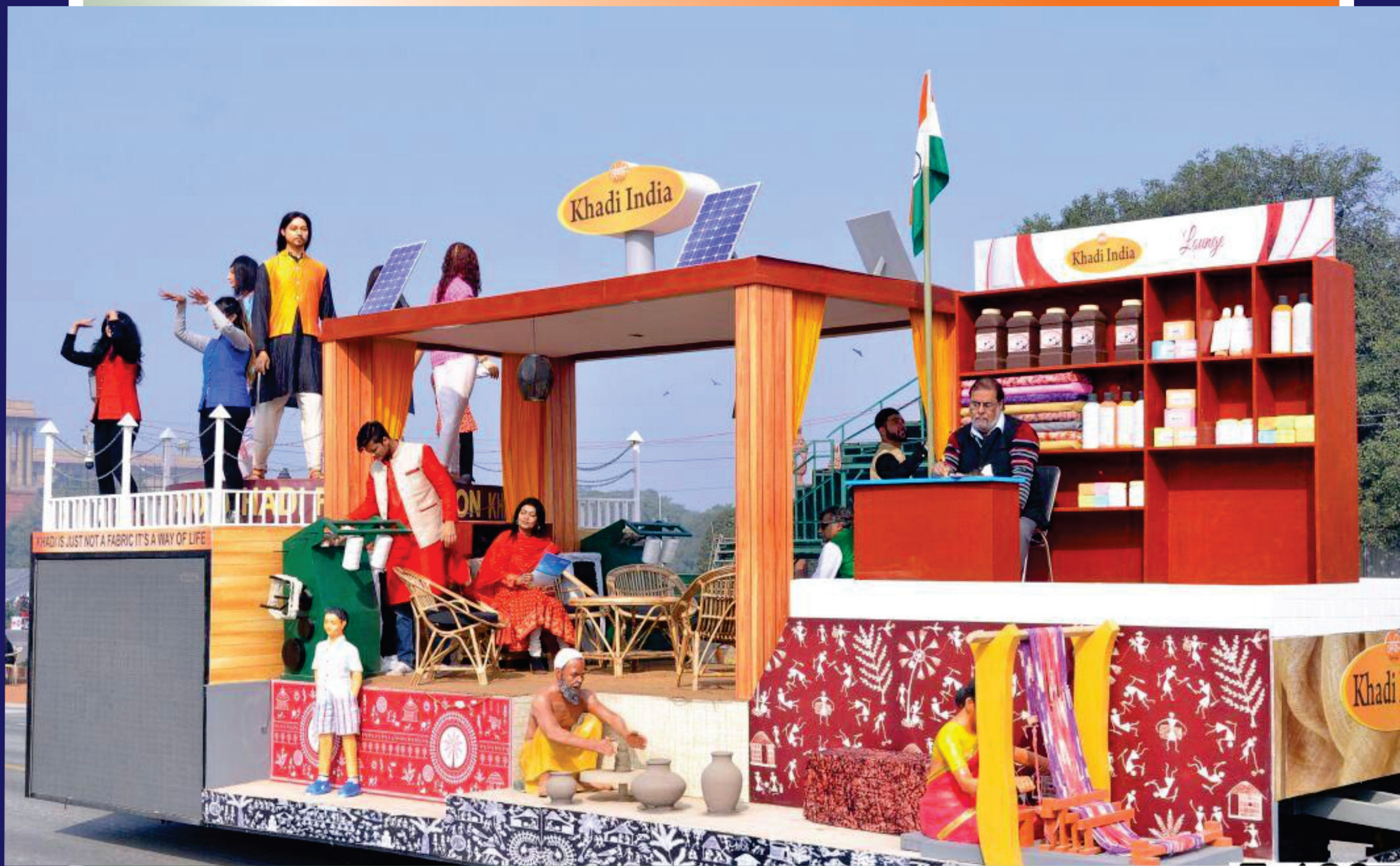

खादी की शोभायात्रा

आठ वर्ष के बाद राजपथ पर खादी की झांकी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 61 अंक 3 मुम्बई फरवरी 2017

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
श्रीमती अन्शु सिन्हा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित

टेलिफैक्सः 022-26719465

ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईटः www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

कामये दुःखतप्तानाम्। प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 24

परेड के लिए तत्पर..................आठ वर्ष के बाद राजपथ पर खादी की झांकी..

वाइब्रेंट गुजरात-2017 में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा खादी पवेलियन का दौरा...

केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना..

केन्द्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा खादी इण्डिया आउटलेट की एक नई श्रृंखला'खादी लाउंज'का उद्घाटन........

जयपुर शहर में पहले खादी लाउंज'का उद्घाटन................

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन ....

मधुमक्खी पालन उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला.......

आयोग द्वारा मधु क्रांति पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन..

श्रीमती अंशु सिन्हा, आई.ए.एस. ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला...........................

आयोग को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को निभाने में हमें सकारात्मक....................

त्रि-पक्षीय लाभ: ओ.एन.जी.सी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मध्य एक नया समझौता.............................

आयोग में 68 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया.................

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि पर दिनांक 30 जनवरी, 2017 को आयोग में मुख्यालय...................

आयोग की 641वीं बैठक का कार्यवृत्त...........................

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां.........25 से 28

परेड के लिए तत्पर...खादी की शोभायात्रा

आठ वर्ष के बाद राजपथ पर खादी की झांकी

खादी की शोभायात्रा का विहंगम दृश्य

स्वदेशी शक्ति की अनुभूति कराती हुई

वाइब्रेंट गुजरात-2017 में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा खादी पवेलियन का दौरा

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जनवरी 2017 को वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भी इस आर्थिक मेले में "वाइब्रेंट गुजरात 2017" में भाग लिया।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने मेले का दौरा किया और माननीय मंत्री ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल के साथ खादी पवेलियन (मंडप) का निरीक्षण किया।

इससे पहले, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी पवेलियन (मंडप) का दौरा किया जहां खादी, पॉलीवास्त्र, रेडीमेड वस्त्र, ग्रामोद्योग उत्पाद, विभिन्न संस्थाओं और पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। इस अवसर पर खादी पवेलियन (मंडप) में बारडोली चरखा और 8 स्पिंडल चरखा का प्रदर्शन भी किया गया।

लखनऊ में राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 'खादी महोत्सव' का आयोजन

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना

दिनांक 24.01.2017 को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने खादी महोत्सव का दौरा किया तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शित खादी के उत्कृष्ट उत्पादों की प्रशंसा की। 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी ग्रामाद्योग प्रदर्शनी 'खादी महोत्सव' का आयोजन दिनांक 14.01.2017 से 28.01.2017 तक लखनऊ के निशातगंज स्थित राजकीय इंटर कालेज मैदान में किया गया।

प्रदर्शनी में प्रदेश एवं विभिन्न प्रान्तों की खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्थाओं ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन किया। खादी महोत्सव में 29 खादी तथा 49 ग्रामोद्योगी संस्थाओं ने क्रमशः 64 व 49 स्टालों पर अपने अपने खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आकर लोगों ने खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों को खरीदा एवं अवलोकन किया । प्रदर्शनी में करीब 1,76,67,129.00 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई ।इससे पहले, खादी प्रदर्शनी का उदघाटन स्वराज आश्रम कानपुर के संचालक व गांधीवादी बृज भूषण पाण्डेय तथा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी (यूपी) श्री आई. पी. पांडे ने किया।

प्रदर्शनी में प्रदर्शित खादी के निर्मित परिधान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जो उन्हें खासा आकर्षित कर रहे थे। स्टालों पर खादी एवं ऊनी परिधान जैसे कोट, पैंट, शर्ट, पैजामा, कुर्ता, लेडीज गारमेंट, कम्बल, रजाई, चादर, हस्त निर्मित रेशम की साड़ियां, रेशम के लेडीज सूट के अलावा आयुर्वेद-हर्बल उत्पाद, सौन्दर्य सामग्री, शहद, आचार, मुरब्बा एवं आंवला के उत्पाद मौजूद थे।

केन्द्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा खादी इण्डिया आउटलेट की एक नई श्रृंखला – 'खादी लाउंज' का उद्घाटन

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आह्वान में यह कहा था कि, आज़ादी से पहले का नारा था "खादी राष्ट्र के लिए, परन्तु अब यह होना चाहिए खादी फैशन के लिए"। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अत्याधुनिक और उच्च श्रेणी के बिक्री केंद्र "खादी लाउंज" की स्थापना कर रहा है जिसमे प्रमुख महानगरों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए डिज़ाइनर परिधानों और विशिष्ट खादी वस्त्रों की श्रंखला प्रदर्शित की जाएगी। इन आउटलट्स के क्रम में पहला आउटलेट 'खादी लाउंज' पूर्ण रूप से सुसज्जित

कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर, विले पार्ले, मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। इन डिजाइनर वस्त्रों में अत्याधुनिक परिधान एवं तैयार वस्त्र शामिल हैं जो कि प्रख्यात् फैशन डिजाइनर रितु बेरी, द्वारा डिजाइन किये गए हैं।

यह स्टोर फैशन के प्रति जागरूक मुंबईकरों और आधुनिक युवाओं के मध्य खादी के हाथ कते आधुनिक वस्त्र, परिधान को विशेष स्थान प्रदान करेगा। इसी प्रकार के उच्च स्तरीय स्टोर दिल्ली और जयपुर में भी स्थापित किए गए हैं और जिनका उद्घाटन इसी माह में किया जायेगा। खादी आउटलेट की लाउंज श्रृंखला को स्थापित करने का उद्देश्य देश के सर्वोत्तम हाथ कते वस्त्र तथा उत्पादों को आधुनिक आउटलेट में प्रदर्शित करना है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री, श्री हरिभाई चौधरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय, मुंबई के अपने प्रथम दौरे पर आयोग के कर्मियों को कहा कि आपके द्वारा

खरीदा गया खादी का मात्र एक वस्त्र एक कारीगर के लिए रोज़गार सृजित करेगा | उन्होंने कहा कि, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कुल 94 प्रतिशत रोज़गार के अवसर सृजित कर रहा है वहीं 4 प्रतिशत रोज़गार सार्वजानिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है | यही नहीं, सकल घरेलु उत्पाद के विकास में कुल 65 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का है | समय के साथ तालमेल करते हुए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की सभी सूचनाओं और विक्रय को डिजिटल रूप में विकसित किया जा रहा है | उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उद्यमियों के दोष शून्य व प्रभाव शून्य आंदोलन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ने भी लागू किया है | जेड ई डी (दोष शून्य व प्रभाव शून्य) प्रमाण पत्र मानक के लिए हमने 50 मानदंड निर्धारित किये हैं | उन्होंने कहा कि, बैंकों को प्रत्येक ब्रांच से एक एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी सृजित करने हेतु निर्देशित किया है | गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए बेहतर प्रतियोगिता का निर्माण एमएसएमई का एक और मुख्य एजेंडा है, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे | इस अवसर पर उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 2017 की डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया |

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'खादी लाउंज दिल्ली, मुंबई और जयपुर में खोले जायेंगे जिसमें प्रीमियम गुणवत्ता वाले सुन्दर, स्टाइलिश खादी सिल्क और आधुनिक डिजाईन किये हुए रेडीमेड वस्त्र रखे जायेंगे जो खादी प्रेमियों को सुखद संतोष प्रदान करेगा। इसके साथ ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'मेक इन इण्डिया' की पहल और प्रधान मंत्री के खादी के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबध्दता की पुष्टि करता है। इससे रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे जोकि ग्रामीण भारत में कारीगरों और विशेष रूप से महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण

आयोग के 2017 के डायरी और कैलेंडर का विमोचन

उत्पादों की बिक्री कर उन्हें सशक्त बनायेंगे। श्री सक्सेना ने इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की खरीदी हेतु कैशलेस भुगतान प्रणाली जैसे- पे टीएम के शुरू करने की जानकारी दी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री उषा ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह पहल हमारे प्रधानमंत्री के खादी को एक फैशन परिधान बनाने के मिशन को पूर्ण करने के लिए की है।

यह लाउंज फैशनपरस्त लोगों की आकांशाओं को पूर्ण करेगा और खादी की बिक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा तथा कारीगरों को सशक्त बना कर उनकी आजीविका को समृद्ध करेगा।

आयोग मुख्यालय, मुंबई में दिनांक 10 जनवरी, 2017 को बैंकरों के साथ पीएमईजीपी योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती उषा सुरेश तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य पाल।

जयपुर शहर में पहले 'खादी लाउंज' का उदघाटन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 17 जनवरी, 2017 को जयपुर के झालना, डुंगरी में स्थित राज्य कार्यालय में खादी लाउंज का उद्घाटन किया | इस बिक्री केंद्र में खादी के विभिन्न सामग्रियां जैसे खादी सिल्क की साड़िया, पश्मीना के आकर्षक वस्तुए इत्यादि प्रदर्शित की जाएँगी | इसी श्रंखला के क्रम में मुंबई में प्रथम खादी लाउंज की शुरुआत की गई है |

अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "इस आउटलेट में बेहतर कर्मचारियों को तैनात करने के साथ इसे आधुनिक बनाने का हमारा प्रयास रहा है। हमने सम्पूर्ण भारत में विगत एक वर्ष में 178 बिक्री केन्द्रों को पुनर्निर्मित किया है | इस प्रकार के बिक्री केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य है बिक्री केंद्र में खरीदी हेतु आने वाले सभी ग्राहकों को अच्छा महसूस कराना | उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि खादी राष्ट्रीय और परंपरागत वस्त्र है | हम चाहते हैं कि हमारे युवा इस हस्तनिर्मित वस्त्र के बारे में समझे तथा धीरे-धीरे इसे स्वीकार करे |

अध्यक्ष महोदय ने आगे यह भी जानकारी प्रदान दी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत सरकार से मनरेगा योजना में खादी उत्पादन को भी शामिल करने का अनुरोध किया है | आयोग केवल नियमित योजना के अंतर्गत केवल 30 दिन का ही रोजगार नहीं देता हैं बल्कि 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है तथा श्रमिकों को दक्ष भी बनाता हैं और इससे कारीगरों के आय में भी वृद्धि होती है |

अध्यक्ष महोदय ने आगे "पारंपरिक चरखा" के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली में शीघ्र ही संग्रहालय में "पारंपरिक चरखा" स्थापित किया जायेगा |

अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी प्रदान की कि जिसके के पास अपना चरखा है वे अपने चरखे को खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दानस्वरूप में दे सकते हैं | इस चरखे को संग्रहालय में उनके नाम के साथ प्रदर्शित किया जायेगा | अभी तक हमने 55 वर्ष से 104 वर्ष पुराने १९ चरखे प्राप्त किये हैं | हमने पालिका बाजार में लगभग 8 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर लम्बा स्टील चरखा भी स्थापित किया है | यह चरखा बारीश और धूप से ख़राब नहीं होगा |

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी में खादी प्रदर्शनी का आयोजन

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के सपनों को पूरा करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं पूर्वी चंपारण जिला खादी और ग्रामोद्योग संघ, मोतिहारी के तत्वावधान में सत्याग्रह चंपारण शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिनांक 30.01.2017 से 13.02.2017 तक नगर भवन, मोतीहारी में राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उदघाट्न माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंहके कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने की। इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र की माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी के अलावा बिहार सरकार के कई विधायक, एमएलसी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन भाषण में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह संबंधी संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि गांधीवादी विचारधारा से ही देश की गरीबी दूर हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों के माध्यम से ही लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मोतिहरी में रोजगार से जोडने के लिए 200

चरखे एवं 20 करघे दिये जाएंगे। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 2016-17 हेतु रू.1.19 करोड की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ने जिन गांवों का दौरा किया था, उन गांवों के 350 कामगारों को सोलर चरखा के प्रशिक्षण हेतु चयन कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोडा जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में आयोग के माध्यम से पीएमईजीपी के अंतर्गत 2430 इकाईयों की स्थापना कर 19624 लोगो को रोजगार प्रदान किया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक 1677 इकाईयों के माध्यम से 10376 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

उन्होंने बताया कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी नगर के प्रवेश द्वार पर गांधीजी के चरखे की स्थापना की जाएगी, जिसे चरखा चौक के नाम से जाना जाएगा, जो चंपारण सत्याग्रह के गौरव का प्रतीक होगा।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में गांधी मैदान, मोतिहारी में विशाल खादी महाकुंभ आयोजित करने हेतु ईच्छा व्यक्त की। उन्होने बताया कि गांधी के इस पुण्यधाम चंपारण को उनके ही सपनों से संजोया जाएगा। उन्होंने सभी खादी संस्थाओं, व्यक्तिगत एवं संभावित उद्यमियों को खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों से अधिक से अधिक जुड कर इस क्षेत्र के विकास में अपना मूल्यवान योगदान देने हेतु आह्वान किया।

इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि बिहार की बंद पडी सभी संस्थाओं को पुनर्जिवित किया जाएगा एवं सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ने जिन गांवों का दौरा किया था, उन गांवो के लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु चरखा, करघा एवं सिलाई इत्यादि कार्यक्रमों से जोडा जाएगा, जिसके लिए आयोग के माध्यम से रूपये 1.00 करोड राशि का आवंटन किया जाएगा।

इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने चंपारण सत्याग्रह एवं गांधीजी के पावन उद्देश्य पर अपना विचार रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उनके सपनों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम माना।

इस महोत्सव/प्रदर्शनी में बिहार एवं दूसरे राज्यों की खादी एवं ग्रामोद्योगी संस्थाएं उनके उत्पादित सूती, रेशमी, ऊनी तथा पोली वस्त्रों जैसे-शर्ट, पैंट, कुर्ता-पैजामा, बंडी, सूती एवं रेशमी साड़ियाँ, चादर, कंबल, सलवार-सूट, अंडी चादर, बेंत-बांस से निर्मित कई घरेलू एवं सजावटी वस्तुएं, चंदन फेस पाउडर एवं चंदन की बनी कई सामग्री, आयुर्वेदिक दवा, सीप से बनी दैनिक एवं सजावटी वस्तुओं, शुद्ध मधु, तेल, पापड़, आचार, सुगंधित अगरबत्ती, फेस पाउडर, साबुन इत्यादि के स्टॉलों के साथ भाग ले रही है। प्रदर्शनी परिसर में कालीन, दरी, डोर मैट्स इत्यादि की बिक्री हेतु अपार भीड़ देखी गयी।

प्रदर्शनी में चरखा से संबंधी जानकारी जीवन्त तकनीकी प्रदर्शनी के माध्यम दी गयी, जिससे आज के युवा वर्ग चरखा से संबंधित जानकारी उत्सुकता पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के जीवन के पूर्ण यात्रा चक्र को तस्वीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए अलग से गॉधी दर्शन हेतु गॉधी पवेलियन का निमार्ण किया गया है।

इस अवसर पर राज्य निदेशक श्री एस.के.गुप्ता ने माननीय मंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को गांधी का प्रतिक चिन्ह ''चरखा'' एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। सभा का संचालन श्री डी.के.राय, सहायक निदेशक ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन आयोग के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.एन.शुक्ला ने दिया।

आयोग द्वारा मधु क्रांति (मधुमक्खी पालन) पर

एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में डिसा में मधु क्रांति के संदर्भ में की गयी चर्चा के बारे में २४ जनवरी २०१७ को मधुमक्खी पालन उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री हरिभाई पी. चौधरी करकमलों से संपन्न हुई। उदघाटन समारोह में श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री अशोक पटेल, माननीय उप कुलपति, सरदार कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाडा, श्री शंकरभाई चौधरी, माननीय राज्यमंत्री, आरोग्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री, गुजरात सरकार तथा प्रमुख बनासडेरी एवं श्री बिपिन पटेल, प्रबंध निदेशक, बनास डेरी, पालनपुर उपस्थित थे ।

कार्यशाला का आयोजन सरदार कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाडा में आयोजित किया गया, जिसमें बनासकॉठा एवं पाटन जिला के करीब 600 किसानों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पुणे से पधारे तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मधुमक्खी पालन उद्योग के संबंध में जानकारी दी गयी ।

स्थानीय सांसद एवं एमएसएमई राज्यमंत्री श्री हरिभाई पी चौधरी ने उपस्थित सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्य हमारे जिलें से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक बजट लाने का आश्वासन दिया । इस अवसर करीब 78 प्रमाणपत्र एवं 10 किट का भी वितरण किया गया ।

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने मधुमक्खी कार्यक्रम के लिए आयोग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री के मधु क्रांति विजन की शुरुआत पाटन-बनासकॉठा जिलें से प्रारंभ होने पर बधाई दी एवं उन्होंने, आयोग से सभी तकनिकी एवं वित्तिय सहयोग देने का अश्वासन दिया।

स्थानीय विधायक तथा गुजरात सरकार के आरोग्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री श्री शंकरभाई चौधरी ने भारत के प्रधानमंत्री के मधु क्रांति आह्वान को पाटन-बनासकॉठा जिलें में अवसर के रुप में लेने को आह्वान किया।

यह कार्यक्रम बनास डेरी, पालनपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, दॉतीवाडा के सहयोग से आयोजित किया गया ।

श्रीमती अन्शु सिन्हा, आई.ए.एस. ने मुरव्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला

श्रीमती अन्शु सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.एच:99) ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 1 फरवरी, 2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित खादी इंडिया में खादी वस्त्रों का अवलोकन किया और ग्रामोद्योगों के अन्य उत्पादों का भी अवलोकन किया। सुश्री सिन्हा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन संपन्न

आयोग को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को निभाने में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से खरा उतरना होगा

-विनय कुमार सक्सेना

मुंबई, 19 जनवरी, 2017: सकारात्मक सोच के साथ सरकार द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा- यह बात आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने मुंबई के सुख होटल में आयोजित आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास भारत सरकार द्वारा दी गयी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अहमियत की पहचान की है, उसे पूरा करने की भी आज हम पर चुनौती है और हमें इस पर खरा उतरना है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले हमें नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनानी होगी और कहना होगा- 'आय केन डू इट' ।

उन्होंने कहा कि आयोग के पास एक बड़ा कार्यदल(फोर्स) है, जिससे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को एक सैनिक की तरह संकल्प लेने की जरूरत है, ताकि वे अपने लक्ष्य पूरा कर सकें। उन्होने आगे कहा कि आयोग में वह क्षमता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, वहां भी रोजगार दे सकता है बस हमें अपने दायित्वों को समझना होगा। उन्होंने कहा, आयोग एक ऐसा संगठन है जो 13,500 रूपये के चरखे एवं 3500 रूपये के करघे पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश से आज भी लोगों को रोजगार दे सकता है और दुनियां में ऐसा कोई भी संगठन यह कार्य नहीं कर सकता है। आज समय है हमें अपने सोच, प्रतिभा और दायित्वों पहचानने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि आयोग को एक नयी पहचान दिलाने में सहयोग तथा सी.एस.आर. कार्यक्रम की अहम भूमिका होगी। अगर आयोग पूरी तरह से इस कार्यक्रम से जुड़ेगा तो पूरे खादी क्षेत्र में एक नयी क्रांति आयेगी। इस बदलाव के साथ हमें कार्य करने की जरूरत है।

उन्होंने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों से कहा कि यह सम्मेलन अपनी बाधाओं को दूर करके नये लक्ष्यों को लेकर जाने के लिए आयोजित किया गया है।

आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वित्तीय सलाहाकार श्रीमती उषा सुरेश ने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने प्रति बहुत आशावादी है, क्योंकि यह इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही है। उन्होंने कहा, जो भी मंत्रालय से बजट मिला है उसे इसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाना है क्योंकि जीएसटी एवं पीएफएमएस स्कीम लागू होने के बाद क्या पैरामीटर्स या मापदण्ड होंगे, यह उस पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

संस्थाओं को गेयरअप करने की जरूरत है, ताकि हम वर्ष 2017-18 के अपने लक्ष्य से पीछे न रह जाय। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल, 2017 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। जीएसटी लागू होने से कुछ दिक्कतें आयेगी उनका हमें सही ढ़ग से हल करना पडेगा। इसके लिए हमें अपनी सभी योजनाओं को आनलाईन करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरे आयोग में एक इंट्रीग्रेटिड फायनेंसिग सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लागू की जा सके।'

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि एमएमडीए योजना का शुभारंभ इसी तिमाही में किया जा रहा है। पिछले वर्ष पीएमईजीपी का लक्ष्य 500 करोड था, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जायेगा। के.आर.डी.पी. योजना के तहत 180 खादी संस्थाओं को लाभ मिला है, जबकि हमारा लक्ष्य 400 संस्थाओं का था। उन्होंने कहा कि योजना में और खादी संस्थाओं को जोडने का प्रयास किया जा रहा है, जिन संस्थाओं के पास 50 से ज्यादा कारीगर हैं उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा। योजना में 600 संस्थाओं को शामिल करने का हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष अबतक 1800 करोड़ रूपये के खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई है। आयोग ने विपणन क्षेत्र में कई नये प्रयास किये हैं, जिसमें ई-कॉमर्श, ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सभी विक्री केन्द्रों को जोडने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस स्कीम के कारण आयोग के विपणन के कार्यो में पारदर्शिता आयी है और बिक्री भी बडी है। उन्होंने यह भी बताया कि आनलाईल खादी प्रमाणपत्र पंजीकरण के तहत अभी तक 40 नयी संस्थाए जुड़ी है।

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. एस. राव ने आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं विपणन क्षेत्र के राज्य स्तर पर दिये गये लक्ष्यों एवं प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों से वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अपने लक्ष्यों को अतिशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी से कहा कि पीएमईजीपी के तहत केवल आवेदन अग्रसरित करने से टारगेट पूरे नहीं होंगे, बल्कि ईडीपी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही मार्जिन मनी का संवितरण होने से ही टारगेट को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मामलों में यह मापदंड निश्चित किया गया है कि ईडीपी कार्यक्रम संपन्न होने की सीमा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है।

श्री वाय.के. बारामतिकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासन ने इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त करते हुए कहा कि आयोग का यह कार्यदल(फोर्स), हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सैनिक की तरह संकल्प लेगा और हम सभी अपने-अपने दायित्वयों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

सम्मेलन के पहले दिन, सभी राज्यों में कार्यान्वित किये जा रहे खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति एवं लक्ष्यों की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों ने अपने-अपने राज्यों में हुई योजनाओं की प्रगति की क्रमवार रूपरेखा प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आने वाली दिक्कतों को सुझाव सहित हल करने का प्रसास किया।

आयोग के राज्य/मण्डलीय निदेशकों का सम्मेलन के दूसरे दिन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बी.एच. अनिल कुमार ने आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वित्तीय सलाहाकार श्रीमती उषा सुरेश की उपस्थिति में पहले दिन में राज्यवार योजनाओं की प्रगति एंव लक्ष्यों की हुई समीक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर संयुक्त संचिव श्री बी.एच. अनिल कुमार ने आयोग के सभी राज्य/मण्डलीय एवं कार्यक्रम निदेशकों को उचित सुझाव देते हुए निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मापदडों के तहत सीमाबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूरा करने का शक्त निदेश दिया।

त्रि–पक्षीय लाभः ओ.एन.जी.सी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मध्य एक नया समझौता

ओ.एन.जी.सी. सामान्यतः अपने कर्मचारियों को देश सेवा व कठिन श्रम के बोनस के रूप में नकद राशि का संवितरण करता है | इस वर्ष ओ.एन.जी.सी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मध्य एक ऐसा समझौता किया कि जिसके अंतर्गत कर्मचारी बोनस में अतिरिक्त लाभ होगा | इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनेआप में एक व्यापक सार्वजनिक हित में योगदान देता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपनी बातचीत में जानकारी दी कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा निर्णय लिया है कि वह अपने कर्मचारियों को नकद राशि से तीन गुना से अधिक मूल्य के पुरस्कार प्रदान करेगा | इस योजना के अंतर्गत, ओ.एन.जी.सी. अपने प्रत्येक नियमित कर्मचारियों को 10,000/- रू.का वाउचर देगा और गैर-नियमित कर्मचारियों को 5000/- रु. का वाउचर प्रदान करेगा | खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन वाउचरों के समक्ष अपने उत्पादों पर 35% अतिरिक्त डिस्काउंट देगा | इस प्रकार उनके कर्मचारियों के नकद मूल्य के 135% बोनस में वृद्धि होगी | इस प्रकार के खादी वाउचरों का ओ.एन.जी. सी. कर्मचारियों द्वारा दो माह के अवधि के अन्दर ही उपयोग में लाया जाना है|

ओ.एन.जी.सी. में 34,236 नियमित कर्मचारी और 1063 अनियमित कर्मचारी हैं कुल 35299 कर्मचारी कार्यरत्त हैं | परिणामस्वरूप इस पहल से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ओ.एन.जी.सी से 35 करोड़ रु. प्राप्त करेगा | खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 35% अतिरिक्त अनुपूरक देने पर विचार करते हुए दो माह की अवधि में आयोग के लगभग 47 करोड़ रु.के उत्पादों की बिक्री होगी है जिसमें 22% की दर से अर्थात 10 करोड़ रु. मजदूरी होगी | अध्यक्ष ने आगे बताया कि इस अवसर पर कारीगरों को विशेष बिक्री अभियान में शामिल किया जायेगा इसके लिए उन्हें 5% पुरुष्कार दिया जायेगा इसे डी.बी.टी. के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा किया जायेगा |

आयोग, ओ एन जी सी के परिसर में 16 प्रदर्शनियों के माध्यम से बेहतर गुणवातायुक्त खादी

उत्पाद प्रदान करेगा | ताकि ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारी अपने कार्यालय में ही प्राप्त कर सकेंगे | आयोग ने निर्णय लिया कि स्थानीय संस्थाए और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाईयां अपने सुसंगत क्षेत्रों में आयोजित प्रदर्शनियों में अपने विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा करने से इसका लाभ स्थानीय कारीगरों को होगा | इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि 70-80% बिक्री रेडीमेड उत्पादों की हो | इसमें विशेष रूप से महिला कर्मचारियों तथा बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा |

इस प्रकार पहली प्रदर्शनी 16 जनवरी, 2017 से 14 फरवरी 2017 तक गुजरात के महसना जिले में आयोजित की गई थी और इसी क्रम में अन्य स्थानों जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, हाजिरा और काम्बे बेसिन क्षेत्र में प्रदर्शनियां आयोजित की जाएगीं, जहाँ ओ.एन.जी.सी. कार्यालय स्थित हैं एवं ओ.एन.जी.सी के सर्वाधिक 11081 कर्मचारी कार्यरत हैं | इसी प्रकार महाराष्ट्र में ओ.एन.जी.सी के 6783 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके लिए राज्य में 16 जनवरी से 28 जनवरी 2017

तक विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की जाएगी इसी तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, झारखण्ड एवं गोवा आदि राज्यों में सूचीबद्ध तरीके से प्रदर्शनियां आयोजित की जाएगी | इन स्थानों के लिए अलग अलग दल गठित किये गए हैं |

त्रि-पक्षीय लाभ के आलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बिक्री, ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मूल्य अनुरूप उत्पाद तथा सद्भाव के

रूप में यह समझौता एक विशिष्ट मोडल के रूप में सिद्ध होगा जो कि ग्रामीण कारीगर समुदाय के स्थाई विकास में सहायक होगा | अधिकतम उत्पादकता के अतिरिक्त ग्रामीण समूदाय अधिकतम मात्रा में अर्जन करेगा तथा इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा | खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस विशिष्ट साझेदारी से अपने खादी कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा तथा आतिरिक्त 6.50 लाख मानव श्रम दिन का भी सृजन करेगा |

व्यापार और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में बहु स्तर पर स्थाई विकास के इस अनुपम प्रयोग का स्वागत किया गया है तथा इस योजना को उत्पादक और उपभोगता के लिए सामाजिक–आर्थिक मोडल के रूप में प्रसारित किया गया है | श्री सक्सेना ने बताया कि इस योजना का प्रतीक-माननीय प्रधानमंत्रीजी का सिद्धांत - 'सबका साथ, सबका विकास' है, जिसे वह अक्सर दोहराया करते हैं |

आयोग में 68 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय मुंबई में आज देश के 68 वे गणतंत्र दिवस को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया | आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री समीर कुमार ने इस अवसर पर कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया | राष्ट्र गान के पश्चात अपने उद्बोधन में उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देते हुए कहा कि, हमने 68 वर्षों में आर्थिक विकास किया है और इस गति को बनाए रखते हुए राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है | उन्होंने कहा कि, गाँधी जी ग्रामीण औद्योगीकरण का सपना देखा करते थे जो आर्थिक औद्योगीकरण से भिन्न है और महात्मा गाँधी जी के सपने को साकार रूप देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनायें व कार्यक्रम अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं , इसकी चर्चा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई बार अपने रेडियो उद्बोधन "मन की बात" में की है | उन्होंने कहा कि, हमारा पूरा प्रयास बेरोजगार को रोज़गार प्रदान करना है |

इस अवसर पर आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों ने देश भक्ति से ओत प्रोत संस्कृतिक प्रस्तुतियां दी |

आयोग के खादी इंडिया आउटलेट, नई दिल्ली में फ्रांस से आये आगंतुक राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करते हुए.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि पर
दिनांक 30 जनवरी, 2017 को आयोग में मुख्यालय, मुंबई में आयोग के कर्मचारियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की

राज्य कार्यालय, अंबाला के निदेशक श्री वी. के. नागर को उनके उद्योग प्रगति में लिखित रूप में योगदान के लिए चाणक्य वार्ता सम्मान-2016 से नवाजा जा रहा है। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी के कर कमलों से श्री नागर जी को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

चाणक्य वार्ता

चाणक्य वार्ता सम्मान, 2016

श्री / श्रीमती / कुमारी .... ने अपने कार्यक्षेत्र .... में उत्कृष्ट कार्य करके समाज के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उपरोक्त कार्य हेतु वर्ष 2016 का 'चाणक्य वार्ता सम्मान' महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री कप्तान सिंह सोलंकी के कर कमलों द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्री कँवरपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न समारोह में मंगलवार 15 नवम्बर, 2016 को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में प्रदान किया गया। विशेष उपस्थिति श्री लक्ष्मी नारायण भाला वरिष्ठ लेखक एवं स्तम्भकार।

आयोग की 641वीं बैठक का कार्यवृत्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 25 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई । उपरोक्त बैठक में आयोग के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्व अंचल), श्री नारायण सी. बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास), श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), सुश्री सुमन लता गुप्ता, उप महा प्रबंधक, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, श्री बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्री दी.पी.एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं आयोग के सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

१) राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन मिशन (हनी मिशन) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्ययोजना तथा इसे मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने के संबंध मे वन आधारित उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन विकास हनी-बी मिशन की कार्ययोजना को रु.859.17 करोड की वित्तीय संरचना के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया, और निर्देशित किया कि आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

क) आयोग ने राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन विकास हनी-बी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना के लिए रु.164.18 करोड़ की वित्तीय संरचना को भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।

ख) आयोग ने वित्तीय सलाहकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के अवलोकनों पर सहमति जताई कि इस मिशन का विस्तार अधिक से अधिक देश के हिमालयी तराई क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होना चाहिए। आयोग ने भी निर्णय लिया कि कार्य-योजना को कार्यान्वित किए जाने के दौरान पुराने मधुमक्खी विस्तार केन्द्रों को पृथक किया जाएगा और नई मधुमक्खी पालन विस्तार केन्द्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

ग) आयोग ने यह भी सलाह दी कि कार्य-योजना को संशोधित करते हुए इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए 1 करोड़ मधुमक्खी पालकों को इस परियोजना से जोड़ने के लक्ष्य के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

घ) आयोग ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री के 'श्वेत क्रांति' कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के बनासकांठा जिले को 'आदर्श मधुमक्खीपालन जिले' के तौर पर विकसित किया जाए।

2) खादी मार्क पंजीयन तथा नए खादी प्रमाणपत्रों के लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रमाणन शुल्क में विसंगति की व्याख्या के संबंध में आयोग ने खादी प्रमाणपत्र निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और व्यक्तिगत, पीएमईजीपी उद्यमियों तथा अन्य पात्र उद्यमों की श्रेणी के लिए खादी मार्क पंजीयन शुल्क को रु.25,000/- से बढ़ाकर रु.50,000/- करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जो लिमिटेड, निजी अथवा साझेदारी कंपनियों अथवा खादी संस्थाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि जब आयोग अस्तित्व में है तो खादी प्रमाणपत्रों को जारी/हस्ताक्षर करने का अधिकार संबंधित अंचलों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बजाय संबंधित आंचलिक समिति के अध्यक्ष के पास होने चाहिए। वर्तमान में प्रमाणपत्रों को संबंधित अंचलों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी/हस्ताक्षर किया जा रहा है।

यह अवगत कराया गया कि एडीबी से सहायता प्राप्त केआरडीपी शर्तों के अनसार, यह निर्णय लिया गया था कि खादी संस्थाओं का प्रमाणन संबंधी कार्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन निदेशालयों को सौंपा जाए।

इसलिए, आयोग ने निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खादी प्रमाणपत्र जारी/हस्ताक्षर करने हेतु उचित प्राधिकार के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसे आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

३) तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने के संबंध में खादी कच्चा माल निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने के संबंध में उल्लेख किया गया था, और दिनांक 14.12.2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए सकारण-आदेश के माध्यम से तीन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केन्द्रीय पूनी संयंत्र, हाजीपुर की सेवाओं में नियमित नहीं करने का अनुसमर्थन किया।

४) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल-अधिकार विलेखों की वापसी की मांग के संबंध में खादी आश्रम, पानीपत द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के बारे में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव आगे उल्लेखित है। आयोग ने मामले पर विचार किया और इस पर अभी तक की गई/प्रारंभ की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया। आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि उक्त संस्था की दान अथवा खरीद के माध्यम से प्राप्त की गई ऐसी सभी संपत्तियों का ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करें, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास गिरवी रखा गया था। उपरोक्त विवरणों को अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य/मंडलीय निदेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खादी संस्थाओं द्वारा संपत्तियों को गिरवी रखे जाने संबंधी सभी विवरणों को कार्यालय के राजस्व प्रलेखों की पंजिका में विधिवत प्रविष्ट किया गया है, ताकि खादी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा संपत्ति को अनियमित/अनधिकृत तौर पर बेचे जाने को रोका जा सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

५) खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी सीसीए विनियम, 2003 की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें अधिसूचित भर्ती नियम-2016 के अनुसार विभिन्न पदनामों में परितवर्तन करने के संबंध में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव इस प्रकार है: आयोग ने नोट पर विचार किया और खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी सीसीए विनियम, 2003 की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें अधिसूचित भर्ती नियम-2016 के अनुसार विभिन्न पदनामों में किए गए परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के संबंध में विधि मामले निदेशालय का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया कि मंत्रालय को इस संबंध में मसौदा अधिसूचना अनुमोदन एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित करे।

६) प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में निदेशकों के ०५ पद को भरने के संबंध में प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की एवं निदेशकों के ०५ पदों क्रमशः विपणन, मीडिया और प्रचार, विधि, टेक्सटाइल एवं प्रशासन और मानव संसाधन क्षेत्र में पे-बैंड 3, वेतनमान रु.15,600-39,100 तथा ग्रेड-पे रु.7,600/- में तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित अर्हता और पात्रता के अनुसार आवेदकों की योग्यता/उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित जांच समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया। जांच समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

जांच समिति:

१.संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : अध्यक्ष
२.निदेशक(विधि) :सदस्य
३.निदेशक(वित्त) : सदस्य
४.निदेशक (लेखा) :सदस्य
५.निदेशक (सूलमउम) :सदस्य
६.उप मु.का.अ (प्रशा एवं मा. संसाधन):सदस्य संयोजक

१. तत्पश्चात, आयोग ने निदेशकों के 05 पदों को भरने हेतु व्यक्तिशः साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों में से योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए निम्नलिखित जांच समिति के मापदण्डों को अनुमोदन दिया। चयन समिति के

सदस्य निम्नानुसार होंगे:

चयन समिति:

१.अध्यक्ष, खाग्राआ : अध्यक्ष

२.संयुक्त सचिव(एआरआई), सूलमउम : सदस्य

३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी :सदस्य

४.श्री राजेन्द्र प्रताप गुप्ता, विशेषज्ञ सदस्य (विपणन), खाग्राआ :सदस्य

५.संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य

६.बाहरी विशेषज्ञ सदस्य (विषय संबन्धित): सदस्य

७.उप मु.का.अ (प्रशासन एवं मानव संसाधन): सदस्य संयोजक

७) आयोग ने केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नई खादी संस्थाओं पर विचार करने हेतु संशोधित चयन मानदंड पर दिनांक १९.१२.२०१६ को जारी परिपत्र की शर्तों में छूट देने संबंधी सुधार कार्यान्वयन प्रभाग निदेशालय के प्रस्ताव पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गयी कि केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जिन ४०० खादी संस्थाओं का सुधार किए जाने का लक्ष्य था, उनमें से अभी तक केवल 235 खादी संस्थाओं को ही सीधी सुधार सहायता जारी की गयी है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है , आयोग ने केआरडीपी के अंतर्गत खादी संस्थाओं के चयन मानदंड की शर्तों में छूट को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:-
- जिन नवीन पंजीकृत खादी संस्थाएं ने अपर्याप्त बैंक वित्त लिया है उन्हें केआरडीपी के अंतर्गत सीधी सुधार सहायता देने पर विचार किया जाएगा।
- नवीन पंजीकृत खादी संस्थाओं को वर्गीकरण से छूट होगी।
- केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत खादी संस्थाओं का उत्पादन टर्न ओवर का औसत पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम 25.00 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए।
- वर्तमान खादी संस्थाओं के पुन:वर्गीकरण के लिए मापदंड की समीक्षा किए जाने की जरूरत है जिससे कि उन्हें केआरडीपी कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिए पात्र बनाया जाए।
- डीआरए के लिए पात्र संस्था हेतु पंजीकृत कारीगरों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए।

8) आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए खादी संस्थाओं के लक्ष्यांक निर्धारित करने हेतु परिपत्र संख्या बीजीटी/बजट दिशा निर्देश 2017-18 दिनांक 16.01.2017 के माध्यम से जारी बजट दिशा-निर्देश के संबंध में सदस्य (मध्य अंचल) की टिप्पणी पर विचार किया, जिसमें परिपत्र के पैरा संख्या 6 में यह उल्लेख है कि खादी संस्थाओं को संबन्धित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य/मंडलीय निदेशक पहले बजट आबंटन जारी करेंगे एवं बाद में सूचना हेतु आंचलिक समिति के साथ बजट आबंटन प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में सदस्य (मध्य अंचल) ने बताया कि एक बार बजट आबंटन को अंतिम रूप दे दिया जाता है एवं राज्य/आंचलिक निदेशक द्वारा उसकी सूचना दे दी जाती है तो फिर उसे आंचलिक समिति के समक्ष रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खादी संस्थाओं को पहले ही आबंटन की सूचना दे देने के पश्चात राज्य/मंडलीय निदेशकों को आंचलिक समिति द्वारा बताए गए संशोधन एवं सुधार को कार्यान्वित करने में परेशानी होगी।

विस्तृत चर्चा के बाद आयोग ने निर्णय लिया कि आंचलिक समिति के अनुमोदन के बाद ही राज्य/मंडलीय निदेशकों द्वारा बजट आबंटन किया जाएगा।

तदनुसार, संदर्भित परिपत्र के पैरा 6 में संशोधन किया गया है और अब इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:-

- "राज्य/मंडलीय निदेशक लक्ष्यांक निर्धारित करने संबंधी बजट कार्य २८ फरवरी, 2017 तक पूरा करेंगे। सीधी सहायता प्राप्त संस्थाओं और राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडलों से सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए पृथक रूप से खादी के लिए समेकित विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 में और ग्रामोद्योग के लिए प्रपत्र-II में भरकर आंचलिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इसे आंचलिक कार्यालयों को 15 मार्च 2017 तक अग्रेषित करना

होगा। केवल आंचलिक समिति के अनुमोदन के उपरांत ही, राज्य/मंडलीय निदेशक सीधी सहायता प्राप्त संस्थाओं और राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडलों से सहायता प्राप्त संस्थाओं के पक्ष में बजट आबंटन जारी करेंगे। आंचलिक समिति गठित न होने की स्थिति में बजट आबंटन आंचलिक उप मु.का.अ के अनुमोदन से जारी किया जा सकता है। इसके बाद समेकित विवरण संबन्धित कार्यक्रम निदेशक को अग्रेषित करने हेतु केंद्रीय कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक भेजा जाएगा"

९) आयोग ने वित्तीय सलाहकार/मु.का.अ, खा.ग्रा.आ की टिप्पणी को नोट किया कि आगे से गुणवत्ता, प्रामाणिकता, पैकिंग, लेबल लगाने, स्वच्छता आदि के लिए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के मूल्यांकन सहित विभागीय बिक्री केन्द्रों से संबन्धित सभी मुख्य विपणन मुद्दों तथा विपणन रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) का पूरी तरह मार्ग-दर्शन लिया जाएगा।

१०) आयोग ने अधिकतम संख्या में खादी संस्थाओं वाले उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में एक मण्डल कार्यालय खोलने की सदस्य (दक्षिण कर्नाटक) की टिप्पणियों को नोट किया।

क) आगे, आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणियों को नोट किया कि मण्डल कार्यालयों को खोलने हेतु एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है और इस प्रकार के कार्यालयों को खोलने के लिए मानदंडों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए, क्योंकि मण्डल कार्यालयों को खोलने के लिए देश भर से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

ख) अतः आयोग ने विस्तृत प्रस्ताव पूरे औचित्य के साथ विचार हेतु आयोग के समक्ष रखने का निर्णय लिया।

११) रांची में आदिवासी कल्याण उप योजना की कार्यशाला :

१. आयोग ने उप मु.का.अ (आयोग प्रकोष्ठ) की टिप्पणियों को नोट किया और रांची में दिनांक 20 और 21 फरवरी को आदिवासी कल्याण उप योजना की कार्यशाला आयोजित करने पर स्वीकृति प्रदान की।

२. आयोग ने सदस्य सचिव (ग्रामीण विकास) के सुझाव को भी नोट किया कि उक्त कार्यशाला के प्रभावशाली आयोजन के लिए कार्यशाला के लिए रखी गयी 5.20 लाख रुपए की राशि अपर्याप्त है एवं इसलिए आयोग ने और अधिक राशि जारी करने की सिफ़ारिश की। आवश्यकता का मूल्यांकन आई.एफ.डी द्वारा किया जा सकता है एवं आवश्यक राशि को पीएमईजीपी, ग्रामोद्योग समन्वय, क्षमता निर्माण एवं प्रचार निदेशालयों से लिया जा सकता है।

३. जैसा कि संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया था, आयोग ने जन जाति कल्याण मंत्रालय एवं जनजाति विकास निगम, ट्राईफेड एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्तीय विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को जन जातियों के कल्याण हेतु इस प्रकार की कार्यशालाओं में सहभागिता हेतु शामिल करने का निर्णय लिया है।

बैठक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ समाप्त हुई एवं आयोग और स्थायी वित्त समिति की अगली बैठक 27 एवं 28 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे अहमदाबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

I. खादी संस्थाओं की लेखा परीक्षा :

१. आयोग ने संयुक्त सचिव की टिप्पणियों को नोट किया कि हाल ही में हुए राज्य निदेशक सम्मेलन, मुंबई में निदेशक (लेखा परीक्षा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई का संस्थागत लेखा परीक्षा करने हेतु लेखा परीक्षा स्टाफ को भेजने संबंधी मामले पर चर्चा की गयी, जहां यह पाया गया कि संस्थाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए निदेशक (लेखा परीक्षा) राज्य कार्यालयों के कर्मचारियों को सीधे ही भेज रहे थे, जिस कारण राज्य कार्यालय स्तर पर काम बधित हो रहा था। आगे, यह भी देखा गया कि लेखा परीक्षा दल कई सप्ताहों तक संस्थाओं में रुके रहते थे, जिस कारण राज्य कार्यालयों को अत्यधिक यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भार उठाना

पड़ता था।

२. अतः आयोग ने मु.का.अ/वि.स की टिप्पणी पर सहमति व्यक्त कि लेखा परीक्षा दल की प्रतिनियुक्ति (१) अंचल से ही की जाएगी और (२) सीमित और निर्धारित अवधि के लिए की जाएगी, जिसमें वे अपने लेखा परीक्षा कार्य को पूरा करेंगे और राज्य कार्यालय के मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

३. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) की टिप्पणियों को भी नोट किया कि राज्य/मंडलीय कार्यालयों सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी कार्यालयों को दिसंबर, 2017 से पूर्व आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

●●

खादी से देश विकास

खिला है संस्कृति का उपवन अब,
बन रहा नया इतिहास।

खादी ग्रामोद्योग मे भी,
नया रंग अब आया है।
चरखा कात रहे मोदी जी,
जनता को मार्ग दिखाया है।

कई बार मन की बातों में,
जन–जन को समझाया है।

चेयरमेन सक्सेना जी ने,
करके काम दिखाया है।

मैडम अंशु सिन्हा आदि ने,
भी तनमन से किया प्रयास।

बिक्री बढ़ी, हो रहा जनता,
के हृदय मे हर्षोल्लास।।

स्वदेशी को अपनाओं भाईयों,
देश की शान बढ़ानी है।

सादा जीवन उच्च विचार यह,
ऋषि मुनियों की वाणी है।

अनेक जातियॉं, अनेक धर्म
अलग–अलग निशानी है।

पर हम सारे एक मॉं के
बेटे हिन्दुस्तानी है।

जगत सिंह हुड्डा की तो,
भाईयों यही है अरदास।

रहो प्रेम से सब मिलजुल के,
देश अपने का करो विकास।।

(श्री जगत सिंह, कार्यकारी, के.वी.आई.सी., अम्बाला)
लेखक हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां

लोकसत्य
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड से प्रकाशित
सत्य के संग, असत्य से जंग
नई दिल्ली, पौष शुक्ल, नवमी, विक्रमी संवत् 2073 | www.epaper.loksatya.com | शनिवार, 07 जनवरी 2017

रंग लाई मेहनत देश में बढ़ गए खादी के दीवाने, खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 9.25 प्रतिशत बढ़ी

'नोटबंदी' में भी जमकर बिकी खादी

■ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देशभर में 7100 बिक्री केंद्रों के माध्यम से बिक्री करता है।

नई दिल्ली, लोकसत्य

नोटबंदी के बावजूद दिसंबर में खादी एवं ग्रामोद्योग की वस्तुओं की बिक्री में सवा नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देशभर में 7100 बिक्री केंद्रों के माध्यम से बिक्री करता है।

आयोग के चेयरमैन वी. के. सक्सेना ने एक बयान में कहा कि 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बावजूद आयोग की बिक्री प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद शुरुआती दो-तीन दिन में बिक्री में कमी देखी गई लेकिन डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यमों को प्रोत्साहन दिए जाने के चलते इसमें जल्द ही सुधार हो गया।

इसके अलावा आयोग ने 2000 रुपये से ज्यादा की डिजिटल खरीददारी करने पर कई तरह की छूट और उपहार की भी घोषणा दी थी। इसके अलावा आयोग ने अपने बिक्री केंद्रों पर डिजिटल भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मुहैया कराई। गौरतलब है कि सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद देश में कई सेक्टर्स, कंपनियों की बिक्री में गिरावट देखी जा चुकी है। ऑटो सेक्टर में कार और 2 व्हीलर्स दोनों सेक्टर्स की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है।

पीएम मोदी भी कर चुके हैं खादी वस्त्रों को खरीदने की अपील

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'मन की बात' कार्यक्रम में खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए अपील कर चुके हैं। पिछले वर्ष मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में कहा, "मैं हमेशा ही लोगों को खादी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आइए, इस गांधी जयंती पर खादी से बने उत्पाद खरीदें जिससे इससे जुड़े गरीबों की मदद हो सके।" पिछले वर्ष लुधियाना में भी एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने खादी खरीदने की अपील करते हुए था कि, "आज जमाना बदल गया है। खादी की गुणवत्ता बदल गयी है। आजादी समय इसका मंत्र था खादी फॉर नेशन, लेकिन अब समय बदल गया है आज मंत्र है खादी फॉर फैशन।"

महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिलाई खादी को पहचान

महात्मा गांधी ने सबसे पहले खादी को पहचान दिलाई थी। सबसे इसका इस्तेमाल करने को कहा था। वे खुद भी चरखा चलाया करते थे। उनके दौर में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इसे अपनाया। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में खादी आंदोलन शुरू किया था जिसका उद्देश्य विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। खादी या खद्दर भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। खादी के वस्त्रों की खासियत होती है कि यह गरमी में शरीर को ठंडक तथा सर्दी में गरमाहट देते हैं।

नव भारत

खादी से सालभर रोजगार की गारंटी

विलेपार्ले में खादी लाउंज का उद्घाटन

शनिवार को राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने विलेपार्ले में अनन्य खादी लाउंज का उद्घाटन किया.

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने केंद्र सरकार के पास केवीआईसी की रोजगार योजनाओं को मनरेगा से जोड़ने का प्रस्तवा भेजा है. केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मनरेगा से केवीआईसी को जोड़ ग्रामवासियों को 100 के बजाए 365 दिनों यानि साल भर का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है.

रोजगार के साथ लोगों की प्रतिदिन आय में भीं वृद्धि की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को 1 दिन के मेहनताने के रूप में 220 रुपए दिए जाते हैं. जबकि केवीआईसी के कारीगर प्रतिदिन 300 से 350 रुपए कमा लेते है. सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी की वजह से लोग खादी से दूर हो गए थे. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1995-96 में देश में कुल 9 लाख चरखे थे. दो दशक के इस समय के दौरान कारीगरों को केवल 18 हजार नए चरखे उपलब्ध करवाए गए हैं. लेकिन मौजूदा सरकार ने खादी कारीगरों की आय बढ़कर खादी उद्योग में जान फूंक दी है.

मुंबई में पहला खादी लाउंज

आयोग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 हजार करोड़ रुपए के बिक्री का लक्ष्य रखा है. जबकि पिछले वर्ष आयोग ने 1 हजार 65 करोड़ के उत्पादों की बिक्री करने में कामयाबी पाई थी. उच्च वर्ग के लोगों को खादी की तरफ आकर्षित करने के लिए केवीआईसी ने मुंबई में अपना पहला खादी लाउंज शुरू किया है. जिसका उद्घटान शनिवार को केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने किया. इसी प्रकार उच्च स्तरीय स्टोर की शुरुआत जनवरी के अंत तक दिल्ली और जयपुर में होने वाला है. खादी लाउंज में प्रीमियम गुणवत्ता वाले स्टाइलिश खादी सिल्क और आधुनिक डिजाइन किये हुए रेडीमेड कपड़ों की बिक्री की जाएगी.

बैंकों को निर्देश

राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि बैंकों के प्रत्येक ब्रांच से एक-एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी सृजित करने हेतु निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कुल 94 प्रतिशत रोज़गार के अवसर सृजित कर रहा है.

लोकसत्ता

'लघु उद्योजकांच्या आर्थिक सक्षमतेची आवश्यकता'

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई

देशाची आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ८४ विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. औद्योगिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महत्वाचे योगदान देणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योजकांना सक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी यांनी 'एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया' व 'एसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्सिल'च्या 'इंडिया एसएमई बिझनेस समिट' परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात केले.

चौधरी म्हणाले की, 'मेक इन इंडिया'च्या वाटचालीत लघु व मध्यम उद्येजकांचा सहभाग वाढविण्याची आवश्यकता असून यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या गुंतवणूक, संयुक्त उद्योग, करारतत्त्वावरील निर्मिती, तंत्रज्ञान प्रसार अशा संधींचा लाभ मिळणार आहे. बँकांनी उद्योगांना आर्थिक सहकार्य उपलब्ध करुन देणे, सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांनी लघु व मध्यम उद्योजकांकडून २० टक्के उत्पादन विकत घेणे, आर्थिकरित्या डबघाइस आलेल्या करखान्याना बँकांनी मदत करणे आणि उद्योजकांना सहकार्य करण्याची हमी सरकारने घेतली असून आपले खाते ते पूर्ण करण्यास कटीबद्ध असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.

जन्मभूमि

કેન્દ્રના સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો ખાતાના રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન હરિભાઇ પરથીભાઇ ચૌધરીએ શનિવારે વિલેપાર્લેમાં આવેલા ખાદી ઍન્ડ વિલેજ કમિશનમાં 'ખાદી ઇન્ડિયા લૉન્જ'નું લોકાર્પણ કર્યું હતું

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां

Khadi dress code for GHMC

STAFF REPORTER

HYDERABAD: In the new year, chances are that the GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation) offices will closely resemble political party headquarters every Monday.

In line with the Government's push to Khadi usage in the State, Commissioner B. Janardhan Reddy has asked the officials of the civic body to wear Khadi clothes to office on the first working day of every week. The message was sent out to the employees on Thursday.

The Commissioner had chosen Monday since meetings with the public and inspections take place on this day and the officials wearing locally made fabric would be apt. A circular in this regard is expected to be released soon.

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
लोकसत्य
दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड से प्रकाशित
सत्य के संग, असत्य से जंग
नई दिल्ली, पौष शुक्ल, अष्टमी, विक्रमी संवत् 2073 www.epaper.loksatya.com शुक्रवार, 6 जनवरी 2017

खादी इंडिया में शुरू हुई पेटीएम से बिक्री

■ दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम से बिक्री के लिए अलग लांज की शुरूआत की गई है

नई दिल्ली, लोकसत्य

खादी इंडिया के शो रूम में अब खादी के वस्त्रों की खरीद का भुगतान पेटीएम से भी किया जा सकेगा। दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम बिक्री के लिए अलग लांज की शुरूआत की गई है।

बृहस्पतिवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि पेटीएम के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि होगी जिससे गरीब खादी कत्तिनों एवं बुनकरों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पेटीएम तीन महीने तक अपनी सेवाए मुफ्त में देगा।

सक्सेना ने बताया कि इससे केंद्र सरकार की पहलों जैसे ई-कामर्स, डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा के शुभारंग के मौके पर खादी ग्रामोद्योग उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण, पेटीएम (मार्केटिंग प्लेस) अध्यक्ष भूषण पाटिल, उपाध्यक्ष सुमिंदर पाल सिंह व खादी इंडिया के प्रबंधक एके गर्ग भी उपस्थित रहे।

खादी इंडिया में शुरू हुई पेटीएम से बिक्री

■ दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम से बिक्री के लिए अलग लांज की शुरूआत की गई है

नई दिल्ली, लोकसत्य

खादी इंडिया के शो रूम में अब खादी के वस्त्रों की खरीद का भुगतान पेटीएम से भी किया जा सकेगा। दिल्ली के रीगल बिल्डिंग स्थित खादी इंडिया में पेटीएम बिक्री के लिए अलग लांज की शुरूआत की गई है।

बृहस्पतिवार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि पेटीएम के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि होगी जिससे गरीब खादी कत्तिनों एवं बुनकरों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पेटीएम तीन महीने तक अपनी सेवाए मुफ्त में देगा।

सक्सेना ने बताया कि इससे केंद्र सरकार की पहलों जैसे ई-कामर्स, डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा के शुभारंग के मौके पर खादी ग्रामोद्योग उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण, पेटीएम (मार्केटिंग प्लेस) अध्यक्ष भूषण पाटिल, उपाध्यक्ष सुमिंदर पाल सिंह व खादी इंडिया के प्रबंधक एके गर्ग भी उपस्थित रहे।

Khadi and Village Industries Commission goes cashless

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Khadi and Village Industries Commission coming under the ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) on Thursday announced to go cashless.

The Commisson President Vinay Kumar Saxena, while inaugurating the facility, said that from now onwards, sale of items in Khadi lounge will be made through Paytm.

The president claimed that the move to go digital will not only facilitate the consumers but will increase the sale of Khadi items. "As per the plan, Paytm will provide free services for the first three months which will attract people towards the lounge," said Saxena.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां

સરકાર દ્વારા એફ.સી.આર.એ. લાયસન્સ રદ કરવામાં આવેલ છે તે વહેલી તકે રિન્યુ કરવા બાબતે રાષ્ટ્રીય દલિત મહાસંઘના બોટાદ જિલ્લા પ્રમુખ વિજયભાઇ પરમારની આગેવાનીમાં કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું.

સાણંદની આર.બી.પટેલ કોલેજમાં વર્ષ દરમ્યાન અનેક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે પણ કોલેજમાં દર વર્ષની જેમ ડેઝ ની ઉજવણી કરાઈ હતી. 30 ડિસે. થી 4 જાન્યુઆરી સુધી બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ડે થી ટ્રેડીશનલ ડે સુધીના તમામ ડેઝ ની ઉજવણી કરાઈ હતી. જેમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. તસવીર-જિજ્ઞેશ સોમાણી

એક્સપ્રેસ બસોની સ્પીડમાં વધારો કર્યો છે. બસમાં આવેલી આ ગતિ મર્યાદાના કારણે ફરજ દરમિયાન એસ.ટી.ના કર્મીઓનાં રનિંગ સમય ઘટાડવવાનો તંત્ર દ્વારા નિર્ણય કરાતા

ઉપપ્રમુખ ગીરીરાજસિંહ ઝાલા, શેશુલ પ્રતિનિધિ આર.આર.ઝાલા, મજૂર મહાજન યુનિયનના મહામંત્રી કિશોરસિંહ પરમાર, કિરીટસિંહ કે.

સુવિધા મોદી સરકારે આ કાર્ય હવે કર્યું, જ્યારે આ સંસ્થા પાંચ વર્ષથી 500 કર્મચારીઓના આધારકાર્ડ લિંક બેંકમાં છે

પાંચ વર્ષથી ઓનલાઇ કર્મીને પગાર ચૂકવતી ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંસ્થા

ભાસ્કર ન્યૂઝ | રાણપુર

બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેર ખાતે ગુજરાતમાં એકમાત્ર ઉની ખાદીનું ઉત્પાદન કરતી ભાલ નળકાંઠા ખાદી ગ્રામોદ્યોગ મંડળ સંસ્થાઓ આવેલી છે. આચ સંસ્થામાં કામ કરતા કર્મચારીઓને આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરી તમામને ઓનલાઈન બેંકમા છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પગાર ચૂકવાય છે. ત્યો આ કામદારો જણાવી રહ્યાં છે કે તેઓને પગારના પૈસા લેવાયા કોઈપણ જાતની અગવતા પડતી નથી.

આ સંસ્થાની સ્થાપના 1958માં 20 કામદારોથી સંતપાલજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી સાથે આ સંસ્થામાં 500 કરતા પણ વધુ કામદારો કામ કરી રોજગારી મેળવી રહ્યાં છે. જેમાં મોટાભાગની મહિલા કામદારો નિષરાધારો અને વૃદ્ધો કામ કરી રહ્યાં છે.

ગુજરાતમાં એકમાત્ર ઉની ખાદીનું ઉત્પાદન કરતી આ સંસ્થામાં સાલ,સ્વેટર, કોટ, ટોપી તેમજ મફલર જેવી વસ્તુઓ હાથકામથી તેમજ ચરખા અને મશીનના ઉપયોગથી મહિલઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ સંસ્થા દ્વારા આજુબાજુના નાગનેશ, સુંદરીયાળ, ખોખરનેશ, દેવળીયા સહિતના આઠથી દસ ગામડાઓમાં સંસ્થા તરફથી કાચો માલ સમાન આપી વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને આ મહિલાઓ મહીને આઠથી દસ હજાર રૂપિયા કપાય છે અને આ તમામ મહિલાઓનો પગાર સંસ્થા દ્વારા બેંકમાં કરવામાં આવે

500 જેટલાં કર્મચારીઓનું આધાર કાર્ડને બેંક સાથે લિંક કરી પગાર ચૂકવતી રાણપુર આવેલી ગ્રામોદ્યોગ સંસ્થા. તસવીર-કેતનસિંહ પરમાર

છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સંસ્થાને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મળે છે. એમડીએ (માર્કેટીંગ ડેવલપમેન્ટ આસીસ્ટન્ટન) સરકારની 65-વધુની કંપની યોજના અંતર્ગત લાભ મળે છે. તેમજ કારીગરના એકાઉન્ટમાં દર ત્રણ મહિને ઉત્પાદન મુજબ પગારના 20 ટકા લેખે સીધી રકમ કારીગરના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત આખામાં ઉની ખાદીનું ઉત્પાદન કરતી આ એકમાત્ર સંસ્થા છે. જેનું વેચાણ દરેક ખાદીગ્રામોદ્યોગ કેન્દ્રના ભંડાર દ્વારા અને સરકાર દ્વારા યોજાતા મેળાઓમાં ફ્રિમાં સ્ટોલ આપવામાં આવે છે અને ત્યાં વેચાણ કરવામાં આવે છે.

નોટબંધીના કારણે ખાદીના વેચાણમાં ઘટાડો થયો

હાલમાં શિયાળાની ઋતુ ચાલુ થઇ હોવાથી આ ઉદ્યોગ ઉપર નોટબંધીની થોડી અસર જોવા મળી છે અને વેચાણમાં દર વર્ષની સરખામણીમાં ઘટાડો થયો છે. બીજી બાજુ અમારી સરકાર પાસે જૂની કોઈ માંગણી પેન્ડીગ નથી પરંતુ સરકારી કર્મચારીઓ જેમકે પીજીપીસીએલના કર્મચારીઓને યુનિફોર્મ આપવામાં આવતી જર્સી, આ જર્સીનો કોન્ટ્રાક સરકાર દ્વારા ખાનગી કંપનીને અપાય છે. આ કામ સંસ્થા પાસે કરાવવા માટે અનેકવાર રજૂઆતો કરાઈ છે.

સંસ્થામાં 500 જેટલા કર્મીઓ કામ કરી રહ્યા છે

અમારી સંસ્થામાં અંદાજે 500 જેટલાં કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે. જેમાં મોટાભાગે મહિલાઓ છે. આ તમામનો પગાલ અમે છેલ્લાં 5 વર્ષથી આધારકાર્ડ લિંક દ્વારા સીધા બેંકમાં જમા કરાવીએ છે. આ વાતનો અમને ખૂબ જ ગર્વ છે.» ગોવિંદસિંહ ડાભી, મંત્રી ખાદીગ્રામોદ્યોગ મંડળ, રાણપુર

KVIC wants Khadi included in MNREGA

NEHA L.M. TRIPATHI
MUMBAI, JAN. 8

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has sent a proposal to the central government, asking it to include Khadi in MNREGA not only to have more artisans under the scheme but also to make unskilled workers earn more through them.

These artisans will train the 5.40 lakh unskilled workers before involving them in Khadi production, thus helping them raise their annual income from ₹20,000 to ₹73,000.

Vinai Kumar Saxena, chairman, KVIC confirmed that a proposal had been sent to the government to have more artisans attached to KVIC and increase employment in the country. Speaking to *The Asian Age*, Mr Saxena said, "Our broader perspective is to have more employment generation for people for a longer time than for a fixed hundred days under the MNREGA scheme. This will not only help unskilled workers learn skills but also help them get stability through selling their products, especially the women of rural India."

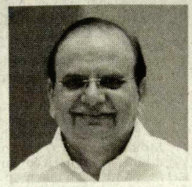

Vinai Kumar Saxena

Haribhai Parthibhai Chaudhary, MoS, ministry of micro, small and medium enterprises (MSME), on his maiden visit to the central office of KVIC said, "Buying one piece of cloth will generate employment for one artisan. As of today, MSME is generating 94 per cent employment and only 4 per cent is being generated by the public sector. Not only this, 65 per cent of GDP growth is from the MSME sector."

खादी को बढ़ावा देने की तैयारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए ड्रेस बना रहा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

अफसर और कर्मचारी सूट-बूट की जगह खादी पहनेंगे

नई दिल्ली | सुहेल हामिद

चमचमाती बहुमंजिला इमारतों में सूट-बूट में काम करने वाले अफसर और कर्मचारी जल्द खादी पहने हुए नजर आएंगे। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के बीच खादी को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग कई कंपनियों के लिए वेशभूषा तैयार कर रहा है। कई कंपनियों से चर्चा अंतिम दौर में है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के बीच खादी को बढ़ावा देने के लिए दफ्तरों में प्रदर्शनी लगाने की भी तैयारी कर रहा है। तेल कंपनी ओएनजीसी समेत विभिन्न कार्यालयों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ओएनजीसी में खादी एवं ग्रामोद्योग की करीब चालीस करोड़ रुपये की खरीदारी होने की उम्मीद है। खादी एवं ग्रामोद्योग ने कुछ दिन पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के कर्मचारियों को जैकेट बना कर दी थी।

अधिकारी का कहना है कि मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के भी संपर्क में है। कई पंचतारा होटल और निजी स्कूलों से ड्रेस तैयार कराने को लेकर बातचीत जारी है।

बढ़ रहा कारोबार

1500 करोड़ रुपये के पार हो गया खादी ग्रामोद्योग आयोग का टर्नओवर वर्ष 2015-16 में

29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई खादी उत्पादों की बिक्री में 2015-16 में 2014-15 के मुकाबले

1170 करोड़ के खादी उत्पाद बिके थे 2014-15 में

एमपी में पहल

31 दिसंबर, 2016 को मध्य प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी कर सरकारी कर्मचारियों-अफसरों को हफ्ते में एक दिन खादी पहनने का आग्रह किया।

संडे अँकर तरुणाईच्या पसंतीनुसार नव्या डिझाइन्सना 'ऑनलाइन'वर वाढता प्रतिसाद

युवांनी दिला खादीचा ग्लोबल 'मंत्रा'

कारागिरांच्या हाताला काम

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां

विले पार्ले में 'खादी लाउंज' का केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी के हाथों उद्घाटन

मुंबई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आह्वान में यह कहा था कि आजादी से पहले का नारा था 'खादी राष्ट्र के लिए, परन्तु अब यह होना चाहिए खादी फैशन के लिए'। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अत्याधुनिक और उच्च श्रेणी के बिक्री केंद्र खादी लाउंज की स्थापना कर रहा है जिसमें प्रमुख महानगरों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए डिजाइनर *परिधानों और विशिष्ट खादी वस्त्रों की श्रंखला प्रदर्शित की जाएगी। इन आउटलेट्स के क्रम में पहला आउटलेट खादी लाउंज पूर्ण रूप से* सुसज्जित कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर, विले पार्ले, मुंबई में स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन श्री चौधरी के हाथों किया गया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि आपके द्वारा खरीदा गया खादी का मात्र एक वस्त्र एक कारीगर के लिए रोजगार सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कुल ९४ प्रतिशत रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। वहीं 4 प्रतिशत रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है यही नहीं, सकल घरेलू उत्पाद के विकास में कुल ६५ प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का है। समय के साथ तालमेल करते हुए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की सभी सूचनाओं और विक्रय को डिजिटल रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उद्यमियों के दोष शून्य व प्रभाव शून्य आंदोलन को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ने भी लागू किया है। जेड ई डी (दोष शून्य व प्रभाव शून्य) प्रमाण पत्र मानक के लिए हमने 50 मानदंड निर्धारित किये हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रत्येक ब्रांच से एक एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी सृजित करने हेतु निर्देशित किया है। गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए स्वास्थ्य प्रतियोगिता का निर्माण एमएसएमई का एक और मुख्य एजेंडा है, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 2017 की डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खादी लाउंज दिल्ली, मुंबई और जयपुर में खोले जायेंगे जिसमें प्रीमियम गुणवत्ता वाले सुन्दर, स्टाइलिश खादी सिल्क और आधुनिक डिजाईन किये हुए रेडीमेड वस्त्र रखे जायेंगे जो खादी प्रेमियों को सुखद संतोष

प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह पहल हमारे प्रधानमंत्री के खादी को एक फैशन परिधान बनाने के मिशन को पूर्ण करने के लिए की है। यह लाउंज फैशनपरस्त लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा और खादी की बिक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा तथा कारीगरों को सशक्त बना कर उनकी आजीविका को समृद्ध करेगा। डिजाइनर वस्त्रों में अत्याधुनिक परिधान एवं तैयार वस्त्र शामिल हैं जो कि प्रख्यात फैशन डिजाइनर रितु बेरी, द्वारा डिजाइन किये गए हैं। यह स्टोर फैशन के प्रति जागरूक मुंबईकरों और आधुनिक युवाओं के मध्य खादी के हाथ कते आधुनिक वस्त्र, परिधान को विशेष स्थान प्रदान करेगा। इसी प्रकार के उच्च स्तरीय स्टोर दिल्ली और जयपुर में भी स्थापित किए गए हैं और जिनका उद्घाटन इसी माह में किया जायेगा। खादी आउटलेट की लाउंज श्रृंखला को स्थापित करने का उद्देश्य देश के सर्वोत्तम हाथ कते वस्त्र तथा उत्पादों को आधुनिक आउटलेट में प्रदर्शित करना है।

खादी के कास्तगार व बुनकर भी है केशलेस

दौसा ,टीएनआईआवाज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कनाडा व इटली से आए हुए दल ने दौसा खादी समिति के ग्राम शेरसिंह रजवास में बैंक के दल ने खादी के कास्तकारों से रूबरू हुए जिसमें उन्होंने देखा की नोटबंदी के चलते उनका पैसे का किस तरह लेन-देन होता है परन्तु जानकारी करने पर वह भी चकित रह गए कि खाद्य समिति द्वारा सभी कास्तकारों के बैंक अकाउंट व उनके द्वारा खादी समिति में किए गए कार्य का पैसा उनके पासबुक में जमा देखकर वह भी खादी समिति के द्वारा केश लेस काश्तकारों का देखकर खाद्य समिति को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि वास्तव में खाद्य समिति के बारे में जितना सुना था उससे कहीं आगे खाद्य समिति है बैंक के दल ने महिलाओं से रूबरू होकर उनकी आमदनी के बारे में भी पूछा तो महिलाओं ने उनके बैंक अकाउंट की पासबुक व समिति द्वारा किये गये कार्य का भी लेखाजोखा जिसकी अलग से डायरी में उनका द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा रहता है उसे देखकर बैंक के प्रबंधक निदेशक ने इस काम के लिए समिति को सराहना की।

PUNYA NAGARI

10 JAN 2017

(MARATHI)

मुंबईत खादी लाऊंजचे दिमाखदार उद्घाटन

मुंबई : खादी ग्रामोद्योग विकास आयोगाच्या खादी वस्त्र प्रावरणे मिळणाऱ्या पहिल्या विशेष 'खादी लाऊंज'चे केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी यांच्या हस्ते शनिवारी मुंबईत उद्घाटन करण्यात आले.

अशा खादी विक्री केंद्रामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. तसेच कारागिरांना विशेष करून ग्रामीण भागातील महिलांना आपल्या उत्पादन विक्रीसाठी सक्षम करता येईल, असे चौधरी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. या खादी विक्री केंद्रामुळे डिझायनर खादी वस्त्र प्रावरणांचे आधुनिक दालन उपलब्ध झाले आहे. यामध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी डिझायनर कपडे आहेत. खादी लाऊंजची दालने देशातील महानगरात उघडण्यात येणार असून या मालिकेतील हे पहिले दालन असून अशा प्रकारची आधुनिक किमती खादी वस्त्रे असणाऱ्या लाऊंजचा प्रारंभ दिल्ली आणि जयपूरमध्येही या महिन्याभरात होणार आहे. फॅशनप्रेमी मुंबईकरांची आवड लक्षात घेऊन आणि आधुनिक काळाचा विचार करून खादी लाऊंजमध्ये वस्त्रांची निवड करण्यात आली आहे. फॅशन डिझायनर रितू बेरी यांनी या वस्त्र प्रावरणांचे डिझायनिंग केले आहे. 'खादी लाऊंज'मुळे हातमागचे सर्वोत्कृष्ट कापड आणि त्या कापडाची वस्त्रे आता आधुनिक दुकानांतून मिळणार आहेत. खादीला जागतिक दर्जा देण्याचे सरकारचे ध्येय असून त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे चौधरी यांनी या वेळी नमूद केले. सरकारने जागतिक बँकेबरोबर २२०० कोटी रुपयांचा करार केला असून येत्या दोन वर्षांत २०१९ पर्यंत कौशल्य विकासाची आणखी १५ तंत्रज्ञान केंद्रे सुरू करणार असल्याचे ते म्हणाले. संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्रातील १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीमुळे छोट्या उद्योगांना लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंद झालेल्या पारंपरिक उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. या आर्थिक वर्षात २००० कोटी रुपयांच्या विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्याद्वारे खादी विणकरांना दिवसाला सात ते साडेसात तास काम मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी सांगितले. खादी उद्योगाला सरकारच्या मनरेगा योजनेशी जोडण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला असून त्याअंतर्गत कौशल्यपूर्ण रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा मंत्रालयाचा प्रयत्न असल्याचे सक्सेना म्हणाले.

Punya Nagari	Khadi India Lounge selling designer clothes launched in Mumbai.

एक चरखे से एक व्यक्ति को मिलता है 330 दिन का रोजगार

मुंबई • संवाददाता

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की पिछली यूपीए सरकार ने उपेक्षा की। 1995-96 में हमारे पास 9 लाख 60 हजार चरखे थे और 21 साल बाद इतनी लंबी अवधि के बावजूद मात्र 16,260 नये चरखे हमें दिये गये हैं। जबकि चरखा हमारा मुख्य टूल है। और एक चरखे से एक व्यक्ति को कम से कम 330 दिन का रोजगार मिलता है। इस प्रकार की जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के विलेपार्ले स्थित परिसर में शनिवार को केंद्रीय राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी के हाथों खादी इंडिया आउटलेट की नयी श्रृंखला 'खादी लाउंज' का उद्घाटन हुआ। इस दौरान जब केवीआईसी के अध्यक्ष सक्सेना से खादी बुनकरों को मनरेगा से जोड़ने की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा,'यह प्रस्ताव अब भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। यदि मनरेगा से खादी और ग्रामोद्योग को जोड़ा जाता है, तो एक बुनकर को 330 दिन का रोजगार मिलेगा और कम से कम एक दिन का 190 रुपये मेहनताना के हिसाब से साल भर उसे 63 हजार रुपये की आमदनी होगी। इसके विपरीत मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को साल भर में महज 20 हजार रुपये ही मिलते हैं।'

हर राज्य की औद्योगिक नीति अलग-अलग है। इसलिए अब हमने हर तीन महीने में सभी राज्यों के इंडस्ट्रियल कमिश्नर की मीटिंग बुलाये जाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की जानकारी केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि इस

बैठक में किस सेक्टर की किस राज्य में औद्योगिक नीति सबसे अच्छी है। इसकी जानकारी दी जायेगी साथ ही जिस राज्य की नीति सबसे अच्छी होगी, उसे अन्य राज्य में भी अमल में लाने के लिए कहा जायेगा। चौधरी ने कहा,'हमारे देश में जितनी इंडस्ट्रिज हैं। उसमें से 94 प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर ही हैं जबकि सिर्फ 6 फीसदी प्राइवेट सेक्टर है। यह सेक्टर सबसे ज्यादा 14 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा देश से कुल जितना निर्यात (एक्सपोर्ट) होता है। उसमें सबसे अधिक 6 हजार प्रोडक्ट एमएसएमई सेक्टर बनाता है।'तेजस के 15 और मंगलयान के 12 पुर्जे एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यापारियों ने बनाये। लड़ाकू विमान 'तेजस' के करीब 15 पुर्जे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े छोटे उद्योगपतियों ने बनाया है। इसी प्रकार मंगलयान का 12 पुर्जा एमएसएमई वालों ने बनाया है। इस प्रकार की जानकारी केंद्रीय राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब हमारी कोशिश रहती है कि विदेश से आने वाले व्यापारियों की प्रतिनिधिमंडल में एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यापारियों की भी मीटिंग हो।

और अत्याधुनिक होगा खादी, छोटे उद्यमियों को मिलेगा लाभ

मुंबई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के तहत मुंबई में भी खादी लाउंज का उद्घाटन किया गया। जहां खादी प्रेमियों के लिए हाथों से बने आधुनिक, डिजाइनर कपड़ों का एक बेहतरीन मंच तैयार किया जा रहा। उक्त विशेष मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री के हाथों किया गया। मंच का उद्देश्य खादी को बढ़ावा देने के साथ ही बेरोजागरों और छोटे उद्यमियों को विकसित करना है।

ज्ञात हो कि गांधी जी के चर्खा परम्पारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आह्वान खादी फैशन के लिए' को साकार करने के उद्देश्य से केवीआईसी ने एक मंच तैयार किया है। जिसका नाम खादी लाउंज रखा गया। जहां हर वर्ग के लोगों की जरुरत के मुताबिक अत्याधुनिक फैशनेबल, अच्छे गुणवक्ता वाले सिल्क रेडीमेड कपड़ों

का समावेश किया गया है। जिसका उद्घाटन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी के हाथों मुंबई विलेपार्ले में स्थित केवीआईसी मुख्यालय में भी किया गया।

प्रेंस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए चौधरी ने बताया कि देशभर में खादी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से जारी है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि खादी में के उत्पादों को अत्याधुनिक करने के लिए हम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे है। जिसके प्रशिक्षण के लिए देश के कई हिस्सों में प्रशिक्षण के केंद्र की स्थापना कर रहे। हमारे प्रयास से देशभर लाखों युवाओं को रोजगार के अलावा उन छोटे उद्यमियों को भी फायदा भी मिलेगा। खादी लाउंज मुंबई के अलावा दिल्ली और जयपुर में भी खोलने की योजना है। वही खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा मिश्रा ने बताया कि आयोग ने यह पहल प्रधानमंत्री के कड़ी को फैशन परिधान बनाने के मिशन को पूर्ण करने के लिए की है। लाउंज फैशनपरस्त लोगों को की जरुरतों को पूर्ण करेगा। साथ ही कारिगरों को रोजगार में वृद्धि करेगा।